राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, रविवार, 19 अप्रैल 2026
वर्ष 14, अंक 358, पृष्ट 04, मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

देशी लौकिया की गौशाला का वीडियो वायरल, गौ भक्तो में आक्रोश...03

पुतिन दिल्ली आ रहे, एक से बढ़कर एक हथियारों के साथ S-500 भी ला रहे...04

लू से तप रहा देश: यूपी के बांदा में रिकॉर्ड तापमान, उत्तर-मध्य भारत में हालात गंभीर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

इस समय देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर देखा जा रहा है। खासकर उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्य इसकी चपेट में हैं। लेकिन अब तक इस सीजन में एशिया का सबसे ज्यादा तापमान है उत्तर प्रदेश के बांदा में 45.4एष्ट दर्ज हुआ। देश में राज्यों की बता करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार , झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हीटवेव का असर देखने को मिला है।

देश का सबसे गर्म जिला रहा बांदा

वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बांदा शुक्रवार को प्रदेश और देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो से तीन दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य एवं ऊपरी क्षोभमंडल में उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ तथा निचले क्षोभमंडल में उत्तर-पश्चिमी राजस्थान से दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बनी द्रोणी का सीमित असर प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में देखा गया, जहां कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई।

आगामी तीन दिनों में अधिकतम बढ़ने की संभावना

हालांकि अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क बना रहा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के प्रमुख शहरों में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में दिन के समय तेज धूप और गर्म पछुआ हवाओं ने जनजीवन प्रभावित किया। कानपुर में शुक्रवार को गर्मी का असर तीखा रहा और सड़कें दोपहर में सूनी नजर आई। यहां अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। लखनऊ में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है और आगामी तीन दिनों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। राजधानी में मौसम शुष्क रहेगा तथा गर्म हवाएं चलने की संभावना है। प्रयागराज में गर्मी और अधिक तीखी रहने के संकेत हैं।

44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है तापमान

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार यहां रविवार तक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रात का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से उमस बढ़ सकती है। झांसी और आसपास के बुंदेलखंड क्षेत्र में लू जैसे हालात बने रहने की संभावना है। बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट जैसे जिलों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने किसानों, श्रमिकों और खुले में कार्य करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले तीन दिनो में बांदा में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है जबकि प्रयागराज में 43 डिग्री से 44 डिग्री,कानपुर में 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने, हल्के सूती वस्त्र पहनने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। यदि शुष्क पछुआ हवाएं इसी प्रकार जारी रहीं तो अप्रैल के शेष दिनों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ सकता है।

अन्य प्रदेश में मौसम का हाल

मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक के जिलों में भी बारिश होगी। जिससे मौमस उमस भरा हो जाएगा। शनिवार सुबह आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में मौसम अचानक बदल गया, यहां सुबह कोहरा छाया है। हालांकि जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट है। वहीं सिक्किम के नाथुला में शुक्रवार-शनिवार को बर्फबारी हुई।

अगले 2 दिन के मौसम का हाल

छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर लू का अलर्ट है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में आंधी और बिजली की आशंका है। झारखंड और ओडिशा में हीटवेव की स्थिति बन सकती है, जबकि तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी रहेगी। ओडिशा में कुछ जगहों पर गर्म रात रहने की संभावना है।अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना में आंधी की आशंका है।

मेट्रो फेज-4 का CM रेखा गुप्ता ने किया औचक निरीक्षण, समय पर काम पूरा करने के निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को मेट्रो फेज-4 के तहत आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और गुणवत्ता, सुरक्षा तथा समय-सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आर के आश्रम मार्ग स्टेशन को एक प्रमुख इंटरचेंज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां ब्लू लाइन और मैजेंटा लाइन के बीच कनेक्टिविटी स्थापित होगी. यह स्टेशन जनकपुरी वेस्ट से आर के आश्रम मार्ग तक फैले 28.92 किलोमीटर लंबे लाइन-8 कॉरिडोर का अहम हिस्सा है. उन्होंने बताया कि फेज-4 के तहत जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन और दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक के कुछ हिस्से पहले ही शुरू किए जा चुके हैं, जबकि बाकी सेक्शन पर तेजी से काम जारी है. यह कॉरिडोर पश्चिम, उत्तर और मध्य दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ेगा, जिससे यात्रा समय घटेगा, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी.

सीएम रेखा गुप्ता ने किया दिल्ली मेट्रो फेज-4 निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने परियोजना की जटिलताओं का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें करीब 7 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल और छह प्रमुख अंडरग्राउंड स्टेशन–डेरावल नगर, घंटाघर, पुलबंगश, सदर बाजार, नबी करीम और आरके आश्रम मार्ग–का निर्माण शामिल है. उन्होंने कहा कि सदर बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में भूमिगत स्टेशन बनाना और सक्रिय रेलवे लाइन व अन्य मेट्रो कॉरिडोर के नीचे टनल बोरिंग करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, जिसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों के बावजूद अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे सतह पर ट्रैफिक या अन्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि भविष्य में मैजेंटा लाइन को आर के आश्रम मार्ग से इंद्रलोक तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे केंद्रीय दिल्ली में कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. इस विस्तार में आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ (9.91 किमी) और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक (11.9 किमी) तक का हिस्सा शामिल है.

दिल्ली मेट्रो राजधानी की लाइफलाइन

परियोजना पूरी होने के बाद बोटैनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक मैजेंटा लाइन की कुल लंबाई करीब 88.4 किलोमीटर हो जाएगी, जिसमें 65 स्टेशन शामिल होंगे. यह ड्राइवरलेस मैजेंटा लाइन दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर बन जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो राजधानी की लाइफलाइन है, जिस पर रोजाना लाखों लोग निर्भर हैं. ऐसे में निर्माण कार्य में गुणवत्ता और सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता. निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि पारदर्शिता बनाए रखते हुए काम की गति तेज की जाए, ताकि तय समय सीमा में परियोजना पूरी हो सके और आम जनता को बेहतर सुविधा मिल सके. उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना के पूरा होने से दिल्लीवासियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी और यह विकसित दिल्ली की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.

संक्षिप्त ख़बरें

बिहार के मुख्य सचिव ने बुलाई अहम मीटिंग, 4 लिगेसी एंड थ्रस्ट जिलों में की विकास कार्यो की समीक्षा

पटना: बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य के चार लिगेसी एंड थ्रस्ट जिलों में शुक्रवार को विकासात्मक मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय जिलों में सुरक्षा और विकास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। समीक्षा में स्पष्ट किया गया कि बिहार राज्य अब नक्सल मुक्त हो चुका है। वर्ष 2020 के बाद से नक्सलियों द्वारा पुलिस पर किसी भी हिंसक हमले की घटना नहीं हुई है। जनवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच सघन अभियानों के तहत 256 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपक 'परियोजना (आरसीपीएलडब्लूईए)योजना के तहत स्वीकृत 153 सड़कों (1980.8 किमी) में से 132 सड़कों (1825.12 किमी) और 74 पुलों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। दूरसंचार संपर्क को सुदृढ़ करने के लिये कई वन स्वीकृति के मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण और जमुई में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय वर्तमान में संचालित हैं। इन विद्यालयों के संचालन को सुगम बनाने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (क्चस्श्वक्च) से संबद्धता पर जोर दिया जा रहा है ।वित्तीय समावेशन के अंतर्गत इन चार जिलों में 782 बैंक शाखाएं कार्यरत हैं, जो पूरे राज्य की कुल शाखाओं का 10 प्रतिशत हैं। बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिये बिहार सरकार की ओर से पंचायत सरकार भवनों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए किराया-मुक्त स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है।

होर्मुज में भारतीय टैंकर पर फायरिंग, MEA ने लिया कड़ा एक्शन, ईरानी राजदूत को किया समन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे दो व्यापारी जहाजों पर फायरिंग हुई है. ये फायरिंग ईरानी नेवी ने की, जिसमें एक भारतीय जहाज पर गोली चलाई थी. इस मुद्दे पर रूख्न में ईरानी राजदूत को समन किया गया है. सरकार ने समन कर भारतीय टैंकर पर हमले का विरोध जताने का संदेश दिया है. बताया जा रहा है कि भारतीय जहाज पर यह हमला ओमान के पास हुआ है. वहीं, भारत के इस सख्त रुख के तुरंत बाद ईरान के राजदूत मोहम्मद फथअली विदेश मंत्रालय पहुंच गए हैं. होर्मुज स्ट्रेट में इराक से लेकर तेज लेकर दो जहाजों पर हमले की बात सामने आई है. ईरान की नेवी ने भारतीय जहाज पर गोली चलाई है. इसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए ईरानी राजदूत को समन भेजा है. सूत्रों के अनुसार, रूख्न ने होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज पर हुए हमले को लेकर चिंता जाहिर की. इस मामले में मंत्रालय ने ईरानी राजदूत डॉ. मोहम्मद फथली को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है. जहाजों पर टैंकरों में करीब 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा है. घटना के बाद क्षेत्र में स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पहले से ही अमेरिका और ईरान के बीच टकराव जारी है और होर्मुज क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है.

ईरान में युद्ध की वजह से कंफ्यूजन की स्थिति

यह विशाल तेल टैंकर होर्मुज के पास से गुजर रहा था तभी उस पर फायरिंग की गई. हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या हताहत की जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं, सूत्र बताते हैं कि इस समय ईरान में युद्ध की वजह से कंफ्यूजन की स्थिति है. ईरान की अलग-अलग सेनाएं और इकाइयां एक-दूसरे से पूरी तरह समन्वय में नहीं काम कर रही हैं. इसी वजह से ये हो रहा है. इससे पहले अमेरिका की तरफ से भी इस युद्ध में अपने ही जहाजों या सहयोगियों पर गलती से फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं.

ईरान ने फिर से बंद किया होर्मुज स्ट्रेट

इससे पहले शनिवार सुबह ईरान ने घोषणा की कि होर्मुज स्ट्रेट अपनी पिछली स्थिति में लौट आया है, यानी उसने एक बार फिर इसे बंद कर दिया गया है. ईरान का कहना है कि उसने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए नाकाबंदी के जवाब में, इस पर होर्मुज स्ट्रेट फिर से कड़ा नियंत्रण लागू कर दिया है. इस घोषणा के बाद, कई वाणिज्यिक जहाजों ने होर्मुज से गुजरने के अपने प्रयास छोड़ दिए हैं. अब कोई भी जहाज इस मार्ग से आगे नहीं बढ़ रहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पूर्व जज ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, जानें क्या है पूरा मामला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली की द्वारका कोर्ट के पूर्व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमन प्रताप सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. दरअसल, अमन प्रताप ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर विरोध दर्ज कराया है. वहीं जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोबेशन पर तैनात एडीजे अमन प्रताप सिंह की सेवा को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. इससे पहले पूर्व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमन प्रताप सिंह की सेवा समाप्ति को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 फरवरी 2026 को दिए अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई दंडात्मक नहीं, बल्कि परिवीक्षाधीन अधिकारी की अनुपयुक्तता के आधार पर की गई टर्मिनेशन सिम्पलिसिटर है. यह मामला Aman Pratap Singh vs Govt Of NCT Of Delhi & Anr से संबंधित है, जिसमें अदालत ने विस्तार से परिस्थितियों का विश्लेषण किया.

वीडियो वायरल होने के बाद किया बर्खास्त

कोर्ट के मुताबिक, अमन प्रताप सिंह की बर्खास्तगी किसी विशेष आरोप में दोषसिद्धि के आधार पर नहीं, बल्कि उनके समग्र कार्य प्रदर्शन और व्यवहार के मूल्यांकन के बाद की गई. बर्खास्तगी का प्रमुख कारण एक वायरल वीडियो बना, जिसमें उन्हें अदालत कक्ष में वकीलों पर चिल्लाते हुए देखा गया था. इस घटना ने न्यायिक गरिमा और आचरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए. इसके अलावा, उनके खिलाफ कुल आठ शिकायतें दर्ज थीं, जिनमें कार्यशैली और व्यवहार संबंधी मुद्दे शामिल थे. आधिकारिक रिकॉर्ड में उनके प्रदर्शन को औसत से कम बताया गया.

दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अमन

अमन प्रताप सिंह की नियुक्ति 28 अप्रैल 2023 को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (DHJS) में हुई थी. वे दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर थे. इस अवधि में अधिकारी के आचरण, निर्णय क्षमता, और पेशेवर व्यवहार का समग्र मूल्यांकन किया जाता है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि निर्णय प्रशासनिक संतुष्टि पर आधारित था, न कि दंडात्मक कार्रवाई के रूप में.

प्रयागराज में 13 लाख की चोरी का खुलासा... तीन आरोपी गिरफ्तार, महंगे शौक ने बनाया चोर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुई 13 लाख की बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया हैं. इस मामले में सिटी जोन की पुलिस ने तीन शातिर चोरों को भी किया गिरफ्तार किया हैं. गिरफ्तार किए गए चोर महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे. चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया था और घर से सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए थे. कोतवाली थाना पुलिस और एसओजी ने ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया हैं जो अपने जरूरत को पूरा करने और महंगे शौक के लिए चोरी की वारदात अंजाम देते थे. पुलिस ने शातिर चोर बब्लू उर्फ नसीर, फिरोज अहमद और साहे आलम उर्फ मोहम्मद शाहिल को गिरफ्तार किया हैं.

पुलिस ने तीन को किया अरेस्ट

अभियुक्तों ने चोरी के रुपए से 22 हजार में पुरानी बाइक और एंड्राइड मोबाइल फोन भी खरीदा था. अभियुक्त साहे आलम उर्फ मोहम्मद शाहिल वादी मुकदमा के घर से कुछ दूरी पर रहता है.उसे परिवार के बाहर जाने और घर बंद होने की जानकारी थी. इसके बाद उसने अपने साथियों को बुलाकर साथियों के साथ 4 अप्रैल को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अभियुक्तों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण और 2 लाख 89 हजार रुपए नगद बरामद किया हैं. चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषणों की कीमत करीब 11 लख रुपए बताई जा रही है. चोरी के पैसों से खरीदी गई एक बाइक ,घटना में प्रयुक्त एक अन्य बाइक और दो ई रिक्शा भी बरामद भी किया गया हैं.

पीड़ित ने दर्ज कराई थी एफआईआर

थाना कोतवाली में मोहित्सिम गंज के उमेश द्विवेदी ने एफआईआर दर्ज कराई थी. उमेश द्विवेदी 3 अप्रैल को लखनऊ चले गए थे. 4 अप्रैल को शातिर चोरों ने बंद घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. तहरीर के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. डीसीपी के मुताबिक अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी थानों में हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी. अभियुक्तों की अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को कुर्क भी किया जाएगा. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है.

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राष्ट्रीय राजधानी को दहलाने की तैयारी में जुटे 4 युवक गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चार ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि ये युवक देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे. हालांकि उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोज लिया. इन चारों आरोपियों को अलग-अलग राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से ढ्डश्वष्ठ बनाने का सामान और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है. पुलिस के मुताबिक ये सभी युवक कट्टरपंथी सोच से प्रभावित थे और नफरत करने के मकसद से काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि ये लोग गजवा-ए-हिंद जैसे खतरनाक विचारों को बढ़ावा दे रहे थे और इसके लिए दूसरों को भी उकसा रहे थे, ताकि अपने नापाक मंसूबों को पूरा कर सकें.

सोशल मीडिया ग्रुप्स में जुड़े हुए थे

जांच में सामने आया है कि ये आरोपी सोशल मीडिया के गुप्त (क्लोज्ड) ग्रुप्स में जुड़े हुए थे, जहां आतंकी विचारधारा, जिहाद और हथियारों की बात होती थी. जांच में पता चला कि इन ग्रुप्स के जरिए ये लोग नए लोगों को जोड़ने और उन्हें भड़काने का काम कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक इनमें से दो आरोपी मिलकर एक रिमोट कंट्रोल IED (बम) बनाने की तैयारी कर रहे थे. इसके लिए जरूरी सामान जैसे बॉल बेयरिंग, कील, खिलौना कार आदि जुटाए जा चुके थे.

लाल किला और इंडिया गेट की रेकी

जांच में यह भी पता चला कि एक आरोपी ने दिसंबर 2025 में दिल्ली आकर लाल किला और इंडिया गेट जैसी महत्वपूर्ण जगहों की रेकी (जांच) की थी. उसने सोशल मीडिया पर लाल किले की फोटो के साथ आपत्तिजनक पोस्ट भी शेयर की थी, ताकि लोगों को भड़काया जा सके. गिरफ्तार युवकों में से एक सोशल मीडिया के जरिए पैसे (क्राउड फंडिंग) जुटा रहा था, जबकि दूसरा हथियार चलाने और ट्रेनिंग दिलाने का वादा कर रहा था. इसके लिए लोगों से पैसे भी मांगे जा रहे थे.

BNS 2023 की धाराओं के तहत मामला दर्ज

चारों आरोपी साधारण परिवारों से आते हैं और ज्यादातर 10वीं तक पढ़े हुए हैं. जांच में पता चला कि इनमें से कोई मैकेनिक है, कोई सिक्योरिटी गार्ड, तो कोई प्लंबर का काम करता है. जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया और कट्टरपंथी भाषणों के प्रभाव में आकर ये लोग गलत रास्ते पर चल पड़े और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए. स्पेशल सेल ने इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

परिसीमन 2026 से क्यों चिंतित हैं दक्षिण भारतीय राज्य?

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में वर्ष 2026 एक निर्णायक मोड़ के रूप में अंकित होने जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया जिसे परिसीमन कहा जाता है वह अब राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन चुकी है। यह प्रक्रिया केवल भौगोलिक सीमाओं के अंकन तक सीमित नहीं है अपितु यह भारतीय संघवाद की आत्मा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के मूल सिद्धांतों को प्रभावित करने वाली है। वर्तमान परिसीमन विधेयक 2026 ने देश के राजनीतिक मानचित्र को पुनः परिभाषित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस विधेयक के केंद्र में जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण है। पिछले कई दशकों से भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 पर स्थिर रही है जिसका आधार 1971 की जनगणना थी। उस समय की जनसंख्या और वर्तमान समय की जनसंख्या के बीच का अंतराल इतना विशाल हो चुका है कि एक सांसद के लिए अपनी विशाल जनता का प्रभावी प्रतिनिधित्व करना कठिन हो गया है। इसी समस्या के समाधान हेतु नए विधेयक में निचले सदन की सीटों की संख्या को बढ़ाकर लगभग 850 करने का प्रस्ताव है। यह विस्तार नए संसद भवन की क्षमता और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक माना जा रहा है। परिसीमन की इस यात्रा को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर दृष्टि डालना अनिवार्य है। भारत में 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से सीटों के पुनर्वितरण पर रोक लगा दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन राज्यों को सुरक्षा प्रदान करना था जिन्होंने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया था। सरकार का मानना था कि यदि केवल जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई गईं तो जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्य राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। इस रोक को पहले वर्ष 2001 तक और फिर 84वें संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब जबकि यह समय सीमा समाप्त हो रही है सरकार ने इस प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसे महिला आरक्षण विधेयक के क्रियान्वयन से जोड़ दिया गया है। वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं। हालांकि इस आरक्षण के प्रभावी होने की पूर्व शर्त परिसीमन की प्रक्रिया का पूर्ण होना है। इस प्रकार परिसीमन अब केवल जनसंख्या का गणित नहीं बल्कि लैंगिक न्याय और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का प्रवेश द्वार भी बन गया है।

विधेयक के प्रस्तुत होते ही देश में एक वैचारिक विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। इन राज्यों का तर्क अत्यंत सुदृढ़ और तर्कसंगत है। उनका कहना है कि पिछले पांच दशकों में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। इसके परिणामस्वरूप वहां जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में काफी कम रही है। यदि अब सीटों का आवंटन केवल जनसंख्या की संख्या के आधार पर होता है तो इन राज्यों की संसद में हिस्सेदारी वर्तमान की तुलना में कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने के कारण उनकी सीटों में भारी वृद्धि होने की संभावना है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें वर्तमान 80 से बढ़कर 140 से अधिक हो सकती हैं वहीं दक्षिण राज्यों की सीटों में भी संख्यात्मक वृद्धि तो होगी किंतु कुल संसद में उनका प्रतिशत हिस्सा घट जाएगा। यह स्थिति दक्षिण के राज्यों को यह संदेश देती है कि उनके द्वारा किए गए विकास और जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों का उन्हें राजनीतिक पुरस्कार मिलने के स्थान पर दंड मिल रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह विवाद सत्ता के संतुलन से जुड़ा है। उत्तर भारत के राज्यों में वर्तमान सत्ताधारी दलों की पैठ अधिक गहरी है। विपक्ष का आरोप है कि सीटों के इस नए वितरण से उन दलों को लाभ होगा जिनका आधार उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्रों में है। इस प्रकार परिसीमन एक निष्पक्ष प्रशासनिक प्रक्रिया के स्थान पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का उपकरण बन सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य की वर्तमान सीटों को कम नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित ढांचे के अनुसार यदि कुल सीटें 850 तक पहुंचती हैं तो दक्षिणी राज्यों की कुल सीटें वर्तमान 129 से बढ़कर लगभग 195 हो सकती हैं। सरकार का तर्क है कि जब हर राज्य की सीटों में वृद्धि होगी तो किसी के साथ अन्याय होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु विवाद का वास्तविक बिंदु कुल संख्या नहीं बल्कि तुलनात्मक शक्ति है। यदि उत्तर भारत की शक्ति दक्षिण के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ती है तो नीति निर्माण और बजटीय आवंटन में उत्तर का प्रभाव अधिक प्रबल हो जाएगा।

आर्थिक मोर्चे पर भी दक्षिणी राज्यों के अपने तर्क हैं। ये राज्य देश के सकल घरेलू उत्पाद में बड़ा योगदान देते हैं और अधिक राजस्व केंद्र को प्रदान करते हैं। उनका मत है कि केवल जनसंख्या को ही प्रतिनिधित्व का आधार मानना आधुनिक शासन व्यवस्था के विरुद्ध है। कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने सुझाव दिया है कि परिसीमन के लिए एक मिश्रित मॉडल अपनाया जाना चाहिए जिसमें जनसंख्या के साथ-साथ शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य संकेतकों और आर्थिक योगदान को भी कुछ महत्व दिया जाए। हालांकि संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करना संवैधानिक रूप से अत्यंत जटिल होगा क्योंकि भारत का लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर आधारित है। किसी भी मतदाता के वोट का मूल्य उसके क्षेत्र की आर्थिक प्रगति या शिक्षा के आधार पर कम या अधिक नहीं किया जा सकता। इस जटिलता के कारण सरकार के सामने एक ऐसी व्यवस्था बनाने की चुनौती है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संघीय संतुलन के बीच सामंजस्य बिठा सके।

परिसीमन आयोग की कार्यप्रणाली भी इस बहस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी अध्यक्षता सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है और इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। आयोग की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इसके द्वारा जारी किए गए आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये आदेश राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप ले लेते हैं। इस अपार शक्ति के कारण विपक्ष ने आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है कि आयोग में राज्यों का अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि क्षेत्रीय चिंताओं को बेहतर ढंग से सुना जा सके। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि संसद यह निश्चित करेगी कि किस वर्ष की जनगणना को आधार बनाया जाए। इससे सरकार को समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की शक्ति मिलती है जो आलोचकों के अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

विधेयक के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करें तो वर्ष 2029 के आम चुनाव भारत के लिए पूरी तरह से भिन्न होंगे। संसद के भीतर का परिदृश्य बदल जाएगा। बढ़ी संख्या में नए सांसदों की उपस्थिति और महिलाओं के लिए आरक्षित 33 प्रतिशत सीटों के साथ भारतीय विधायी ढांचे का चेहरा बदल जाएगा। यह परिवर्तन केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक भी हो सकता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नीति निर्माण में अधिक संवेदनशीलता और सामाजिक विषयों पर अधिक ध्यान दिए जाने की अपेक्षा है। किंतु इस उज्ज्वल पक्ष के साथ क्षेत्रीय असंतुलन का काला बादल भी मंडरा रहा है। यदि उत्तर और दक्षिण के बीच का राजनीतिक अंतराल बढ़ता है तो यह भारत की एकता और अखंडता के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकता है। संघीय ढांचे में राज्यों का विश्वास बनाए रखना केंद्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए व्यापक परामर्श और संभवतः संविधान के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा की शक्तियों में वृद्धि जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है ताकि दक्षिण के राज्यों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। निष्कर्षतः परिसीमन विधेयक 2026 केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं है बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के अगले अध्याय की पटकथा है। इसमें एक ओर जनसंख्या के आधार पर न्यायोचित प्रतिनिधित्व देने की आकांक्षा है तो दूसरी ओर संघीय संतुलन बिगड़ने का वास्तविक भय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या का महत्व सर्वोपरि है परंतु विविधतापूर्ण राष्ट्र में सभी क्षेत्रों की भावनाओं का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। आने वाले वर्षों में यह देखना रोचक होगा कि भारत सरकार और राजनीतिक दल इस संवैधानिक अनिवार्यता और क्षेत्रीय न्याय के बीच कैसे संतुलन साधते हैं। अंततः सफलता उसी मॉडल में निहित होगी जो भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अनुभव कराए कि संसद में उसकी आवाज और उसके राज्य का महत्व अक्षुण्ण है चाहे वह भौगोलिक रूप से कहीं भी स्थित हो। यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता की परीक्षा है जो यह तय करेगा कि आने वाले दशकों में देश का संघीय ढांचा कितना सुदृढ़ और समावेशी होगा। 2026 का यह मोड़ भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाला एक ऐतिहासिक क्षण सिद्ध होने जा रहा है।

महेन्द्र तिवारी

जब घर ही कब्र बन गया और रिश्ते खामोश गवाह

[अपनों के बीच भी अजनबी बनकर दम तोड़ती एक जिंदगी]

[इंसानियत की दरारें: एक मृत्यु जो पूरे समाज पर सवाल छोड़ गई]

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के नगीन नगर (चंदन नगर थाना क्षेत्र) की तंग गलियों में जब लंबे समय से जमी खामोशी अचानक दरक गई, तो उसके भीतर छिपा भयावह सच पूरे इलाके को भीतर तक हिला गया। एक बंद और उपेक्षित मकान से निकली सड़न और रहस्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को सन्न कर दिया। इसी मकान के भीतर 65 वर्षीय वृद्ध का निर्जीव शरीर कुछ दिनों (लगभग दो दिन) से पड़ा हुआ था, और समय के साथ वह उपेक्षा की भयावह तस्वीर बन चुका था। यह घटना केवल मृत्यु की सूचना नहीं थी, बल्कि टूटते रिश्तों, बिखरते परिवार और संवेदनहीन होते समाज का दर्दनाक दर्पण थी। बंद दीवारों के भीतर दबी यह चुप्पी अब एक कठोर प्रश्न बनकर खड़ी है—क्या इस आधुनिक युग में इंसान अपने ही घर के भीतर इतना अकेला और असहाय हो सकता है?

सन्नाटे में दबी हुई सच्चाई जब अचानक सांस लेने लगती है, तो उसका पहला स्पर्श ही पूरे वातावरण को हिला देता है। कॉलोनी के बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी गेंद अचानक उसी बंद पड़े पुराने मकान के भीतर जा गिरी। गेंद लेने गए बच्चों ने जैसे ही अंदर झांका, तेज दुर्गंध और सड़न की भयावह स्थिति ने उन्हें भयभीत कर दिया। भीतर का दृश्य अत्यंत भयावह था—चूहों द्वारा क्षत-विक्षत शव और मौत का गहरा सन्नाटा। यह सच शायद और भी दिनों तक छिपा रहता, यदि वह गेंद उस बंद मकान में न जाती, जिसने एक अनदेखी और उपेक्षित त्रासदी को उजागर कर दिया। सूचना मिलते ही चंदन नगर थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, जहां भीतर का दृश्य अत्यंत भयावह और दिल दहला देने वाला था—कमरे में फैली सड़ांध, जड़ हो चुकी खामोशी और लंबे समय से उपेक्षित वातावरण यह स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि मृत्यु कई दिन पहले हो चुकी थी और किसी ने उसकी सुध नहीं ली थी; शव काफी विकृत अवस्था में था, जिससे यह घटना केवल एक पुलिस जांच का विषय न रहकर समाज की संवेदनहीनता और टूटते पारिवारिक संबंधों का कठोर दर्पण बन गई, और सबसे बड़ा प्रश्न यही रह गया कि तीन पुत्रों के होते हुए भी यह व्यक्ति अपने अंतिम समय में इस तरह पूर्णतः अकेला क्यों रह गया। जीवन की कठिन धूप में तपकर यह वृद्ध व्यक्ति वर्षों तक मेहनत-मजदूरी करता रहा और अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को कंधों पर ढोता हुआ बच्चों के भविष्य को संवारने में पूरी उम्र खपा दी; अभावों और आर्थिक संघर्षों के बीच भी उसने कभी घर की डोर को टूटने नहीं दिया और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा। समय के साथ शराब की लत ने उसके जीवन को अवश्य प्रभावित किया, लेकिन पिता के हृदय में बसे स्नेह और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद कभी कम नहीं हुई, जबकि विडंबना यह रही कि वही बच्चे धीरे-धीरे उससे दूर होते चले गए; त्याग, उपेक्षा और टूटते रिश्तों के बीच यह पवित्र सा बंधन अंततः बिखरकर एक दर्दनाक मौन में बदल गया।

तीन पुत्रों के होते हुए भी यह वृद्ध व्यक्ति अपने अंतिम समय में गहरी एकाकी स्थिति में था; वर्षों से चले आ रहे पारिवारिक मतभेदों ने रिश्तों की नींव कमजोर कर दी थी, जिसके कारण न कोई मुलाकात बची, न कोई हालचाल लेने वाला और न ही कोई जिम्मेदारी निभाने वाला शेष रहा। जिस पिता ने जीवन भर अपनी संतान के भविष्य को संवारने में अपना सब कुछ लगा दिया, वही अंततः उपेक्षा का शिकार बन गया; कभी स्नेह और अपनत्व से भरे रक्त संबंध धीरे-धीरे दूरी, नाराज़गी और स्वार्थ में बदल गए। यह स्थिति बताती है कि समय के साथ कई रिश्ते भावनाओं से टूटकर केवल औपचारिक औपचारिकता भर रह जाते हैं। मृत्यु की सूचना मिलने के बाद जब रिश्तेदारों और पुत्रों को खबर दी गई, तो उनका व्यवहार और भी अधिक पीड़ादायक और निराशाजनक था; एक-एक कर सभी ने आने से स्पष्ट इनकार कर दिया, मानो अंतिम संस्कार कोई पारिवारिक दायित्व नहीं बल्कि एक अनचाहा बोझ हो। एक ओर वृद्ध पिता का निर्जीव शरीर पड़ा था, तो दूसरी ओर पुत्रों की संवेदनहीनता और दूरी साफ झलक रही थी। आश्चर्यजनक रूप से संपत्ति को लेकर सक्रियता तो दिखाई दी, लेकिन भावनाओं, कर्तव्य और मानवीय संवेदना का पूर्ण अभाव उजागर हो गया। यह पूरा दृश्य रिश्तों के पतन और सामाजिक मूल्यों के क्षरण की सबसे कठोर और असहज तस्वीर प्रस्तुत करता है।

नगीन नगर, इंदौर की यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है; आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में मोबाइल, काम और व्यक्तिगत स्वार्थ ने पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट को लगातार कमजोर कर दिया है। बुजुर्ग घरों में अकेलेपन का जीवन जीने को मजबूर हैं, जिनकी देखभाल और हालचाल लेने वाला कोई नहीं बचा। यह घटना उस गहराते सामाजिक संकट को उजागर करती है, जहां इंसान मौजूद होते हुए भी इंसानियत धीरे-धीरे खोती जा रही है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति और भी भयावह रूप ले सकती है। यह घटना एक गहरी सामाजिक पीड़ा और विचारणीय सच्चाई को उजागर करती है, जिसे नज़रअंदाज़ करना अब संभव नहीं है। जीवन की वास्तविक संपत्ति न तो धन है और न ही भौतिक सुख-सुविधाएं, बल्कि रिश्तों की गरमाहट, सम्मान और अपनापन ही उसका असली आधार हैं। यदि हम आज अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं, तो यही उपेक्षा कल हमारे अपने जीवन में भी लौट सकती है। यह प्रसंग स्पष्ट चेतावनी देता है कि रिश्तों को समय रहते समझना, संवारना और निभाना ही सबसे बड़ी मानवीय जिम्मेदारी है। अन्यथा अंत में केवल पछतावे का अंधकार शेष रह जाएगा और समाज धीरे-धीरे उस संवेदनहीन दिशा में बढ़ता जाएगा, जहां इंसान होते हुए भी इंसानियत का अर्थ खोने लगता है।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

मिलावट का महाजाल, थाली से लेकर शरीर तक फैलता धीमा जहर,सूरत का खुलासा एक चेतावनी, देशभर में मिलावट की भयावह सच्चाई

सूरत के सचिन जीआईडीसी में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़ केवल एक स्थानीय अपराध नहीं, बल्कि पूरे देश में फैले मिलावट के संगठित नेटवर्क की गंभीर तस्वीर पेश करता है। 1 किलो शुद्ध घी से 15 किलो नकली घी तैयार करने की तकनीक न सिर्फ कानून का मजाक उड़ाती है, बल्कि आम जनता की सेहत के साथ खुला खिलवाड़ भी है। 'विदुर' जैसे नामों के पीछे छिपा यह जहर देश के कई राज्यों तक पहुंच रहा था, जिससे यह साफ हो जाता है कि मिलावट का कारोबार अब छोटे स्तर की धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक बड़ा और संगठित उद्योग बन चुका है।

भारत में खाद्य मिलावट की समस्या नई नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी गंभीरता और विस्तार दोनों तेजी से बढ़े हैं। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, देश में जांच किए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों में से एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में मिलावटी पाया जाता है। कई राज्यों में यह आंकड़ा 20 से 30 प्रतिशत तक पहुंच जाता है, जो बेहद चिंताजनक है। दूध, घी, तेल, मसाले, मिठाइयां, यहां तक कि फल और सब्जियां भी इस जाल से अछूती नहीं हैं। मिलावट अब केवल गुणवत्ता की कमी नहीं रही, बल्कि यह सीधे-सीधे स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुकी है।

मुनाफे की अंधी दौड़ में मिलावटखोरों ने इंसानियत को ताक पर रख दिया है। सूरत के इस मामले में जिस तरह केमिकल, पामोलीन ऑयल और सिंथेटिक फ्लेवर का इस्तेमाल कर नकली घी तैयार किया जा रहा था, वह दिखाता है कि अपराधी कितनी वैज्ञानिक और योजनाबद्ध तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टरों की तरह सिरिंज का इस्तेमाल कर केमिकल की सटीक मात्रा मिलाना इस बात का प्रमाण है कि यह काम केवल अवैध ही नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक भी है। ऐसे उत्पाद दिखने और महकने में भले ही असली जैसे लगें, लेकिन इनके सेवन से शरीर के अंदर धीरे-धीरे जहर फैलता है।

मिलावटी खाद्य पदार्थों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इनके दुष्प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देते। यह धीरे-धीरे शरीर को कमजोर करते हैं और गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। हृदय रोग, किडनी फेल होना, लिवर डैमेज, कैंसर जैसी घातक बीमारियां लंबे समय तक मिलावटी भोजन के सेवन से जुड़ी हुई हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर और भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। यही कारण है कि मिलावट केवल एक आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सीधा हमला है।

आज स्थिति यह हो गई है कि आम उपभोक्ता के लिए असली और नकली के बीच अंतर करना बेहद मुश्किल हो गया है। आकर्षक पैकेजिंग, ब्रांडेड लेबल और सस्ते दामों के लालच में लोग अनजाने में ही मिलावटी उत्पाद खरीद लेते हैं। सूरत के मामले में भी 'विदुर' ब्रांड के नाम पर नकली घी को असली बताकर बेचा जा रहा था, जिससे उपभोक्ता आसानी से धोखा खा जाते थे। यह प्रवृत्ति केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर कोने में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। मिलावट का यह जाल केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों तक भी फैल चुका है। थोक व्यापारियों और सप्लाई चेन के जरिए यह नकली सामान दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचाया जाता है। कई बार स्थानीय दुकानदार भी अनजाने में ऐसे उत्पाद बेचते हैं, जिससे यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम करता है, जिसमें निर्माता, सप्लायर और वितरक सभी शामिल होते हैं। इस समस्या की जड़ में कमजोर निगरानी व्यवस्था और कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना भी शामिल है। हालांकि देश में खाद्य सुरक्षा के लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन सख्ती से नहीं हो पाता। जांच की प्रक्रिया धीमी होती है और दोषियों को सजा मिलने में लंबा समय लग जाता है, जिससे उनके हौसले बुलंद रहते हैं। कई मामलों में जुर्माना भी इतना कम होता है कि वह उनके मुनाफे के सामने नगण्य साबित होता है।

ऐसे में जरूरी है कि मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कानूनों को और सख्त बनाया जाए, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिले और दूसरों के लिए यह एक उदाहरण बन सके। साथ ही, खाद्य पदार्थों की नियमित और व्यापक जांच होनी चाहिए, जिससे बाजार में बिकने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। तकनीक का उपयोग कर ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत बनाना भी समय की जरूरत है।

सरकार के साथ-साथ उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। लोगों को जागरूक होना होगा और सस्ते के लालच से बचना होगा। विश्वसनीय ब्रांड और प्रमाणित उत्पादों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही, यदि किसी उत्पाद की गुणवत्ता पर संदेह हो तो उसकी शिकायत संबंधित विभाग में करनी चाहिए। जागरूक उपभोक्ता ही इस समस्या से लड़ने में सबसे बड़ा हथियार बन सकता है।

सूरत का यह कांड एक चेतावनी है कि अगर समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो इसके परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। यह केवल एक शहर या एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश की चुनौती है। मिलावट का यह जहर हमारी थाली में घुलकर हमारी सेहत को धीरे-धीरे खत्म कर रहा है। अब समय आ गया है कि इस समस्या को गंभीरता से लिया जाए और मिलकर इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन मिल सके।

कांतिलाल मांडोत

अनिवार्य मतदान जन जागरूकता की आवश्यकता और लोकतंत्र की सुदृढ़ता

भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है जहां जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार केवल एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब नागरिक मतदान करते हैं तब वे अपने भविष्य की दिशा तय करते हैं और शासन व्यवस्था को आकार देते हैं। इसके बावजूद यह एक गंभीर सच्चाई है कि देश में बड़ी संख्या में लोग मतदान से दूर रहते हैं। यही कारण है कि अनिवार्य मतदान और जन जागरूकता की आवश्यकता आज अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गई है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम में यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि यह किसी एक दल का विषय नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का विषय है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि इस निर्णय को राजनीति के तराजू पर न तौला जाए बल्कि इसे देशहित में देखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विपक्ष श्रेय लेना चाहता है तो वह ले सकता है लेकिन महिलाओं के अधिकारों को रोका नहीं जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने वाला है। दूसरी ओर कई विपक्षी नेताओं ने इस विषय पर शंका और विरोध प्रकट किया। प्रियंका वाड्रा ने इसे राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित बताया जबकि अखिलेश यादव ने इसे केवल नारे तक सीमित बताया। इसी प्रकार कपिल सिब्बल ने भी सरकार की मंशा पर प्रश्न उठाए। लोकतंत्र में प्रश्न उठाना आवश्यक है लेकिन हर विषय पर बिना ठोस आधार के विरोध करना उचित नहीं है। जब कोई निर्णय व्यापक जनहित से जुड़ा हो तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए।

यहीं पर अनिवार्य मतदान का महत्व सामने आता है। यदि प्रत्येक नागरिक के लिए मतदान करना अनिवार्य हो जाए तो लोकतंत्र और अधिक सशक्त हो सकता है। इससे नागरिकों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। लोग केवल दर्शक बनकर नहीं रहेंगे बल्कि सक्रिय भागीदार बनेंगे। इससे शासन व्यवस्था अधिक प्रतिनिधिक और संतुलित बनेगी। भारत में यह देखा गया है कि कई बार शिक्षित वर्ग भी मतदान के प्रति उदासीन रहता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी अधिक होती है। यह स्थिति बताती है कि समस्या केवल संसाधनों की नहीं बल्कि सोच की भी है। इसलिए आवश्यक है कि समाज के हर वर्ग तक यह संदेश पहुंचे कि मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। जब तक यह भावना विकसित नहीं होगी तब तक लोकतंत्र की जड़ें पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाएंगी। अनिवार्य मतदान लागू करने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। विद्यालयों महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों को यह समझाना होगा कि उनका एक मत कितना महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति यह समझेगा कि उसका मत देश की दिशा तय कर सकता है तब वह स्वेच्छा से मतदान के लिए प्रेरित होगा।

सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान प्रक्रिया सरल और सुगम हो। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसी भी नागरिक को मतदान करने में कठिनाई न हो। पारदर्शिता और निष्पक्षता भी उतनी ही आवश्यक है क्योंकि जब लोगों का विश्वास चुनाव प्रक्रिया में बना रहेगा तब ही वे अधिक संख्या में भाग लेंगे। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक सशक्त विपक्ष सरकार को जवाबदेह बनाता है और नीतियों में सुधार लाने में मदद करता है। लेकिन जब विपक्ष हर विषय पर केवल विरोध करता है तो उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। जनता यह समझने लगती है कि विरोध तर्क पर आधारित नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित है। इसलिए विपक्ष को चाहिए कि वह रचनात्मक भूमिका निभाए और जहां आवश्यक हो वहां समर्थन भी दे। महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे विषय केवल राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के माध्यम भी हैं। यदि इन पर सहमति बनती है तो यह देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया यह संदेश कि यह लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए वास्तव में सार्थक है क्योंकि लोकतंत्र में सामूहिक निर्णय ही सबसे प्रभावी होते हैं।

अनिवार्य मतदान इस पूरी प्रक्रिया को नई दिशा दे सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर नागरिक अपनी भूमिका निभाए और लोकतंत्र केवल कुछ लोगों तक सीमित न रह जाए। इससे सरकारों को भी जनता की वास्तविक इच्छाओं के अनुसार काम करना पड़ेगा क्योंकि हर मत महत्वपूर्ण होगा। अंततः यह समझना आवश्यक है कि लोकतंत्र केवल अधिकारों का नाम नहीं है बल्कि यह कर्तव्यों का भी समुच्चय है। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए यह समय है कि अनिवार्य मतदान जैसे विचारों पर गंभीरता से विचार किया जाए और जन जागरूकता को व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाए। विपक्ष को भी यह समझना चाहिए कि बेवजह विरोध करना लोकतंत्र के हित में नहीं है। यदि कोई निर्णय देश और समाज के लिए लाभकारी है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। स्वस्थ बहस और रचनात्मक आलोचना लोकतंत्र की पहचान है लेकिन केवल विरोध करना उचित नहीं है। जब हर नागरिक जागरूक होगा और अपने मताधिकार का उपयोग करेगा तब ही भारत का लोकतंत्र वास्तव में सशक्त और जीवंत बन पाएगा। अनिवार्य मतदान और जन जागरूकता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।

कांतिलाल मांडोत

भीषण प्रचंड गर्मी से बेहाल प्रदेश के सरकारी स्कूल

देश के अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में भी भीषण गर्मी ने अपना तांडव मचा रखा है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल के अंत तक लू और प्रचंड गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना है। एक और राज्य सरकारें लोगों को गर्मी से बचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं सरकारों के आदेश से हर वर्ष अप्रैल माह में स्कूलों का संचालन जारी रहता है। नर्सरी से बारहवीं तक के बच्चे तपती दोपहरी में स्कूल से घर लौटते नजर आते हैं। सरकारें भले ही स्कूलों का समय दोपहर 12 बजे तक सीमित करने के निर्देश जारी करती हैं, लेकिन वास्तविक समस्या इससे कहीं अधिक गंभीर है। मध्यम और निम्न वर्ग के अधिकांश बच्चे पैदल, साइकिल या ऑटो से स्कूल आते-जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई बच्चों को कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में जब स्कूलों की छुट्टी दोपहर 12 बजे के बाद होती है, तब बच्चों को अपने घर पहुँचने में डेढ़ से दो घंटे तक का समय लग जाता है, जो दिन का सबसे अधिक गर्म और खतरनाक समय होता है। इस दौरान लू और तेज धूप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों से आने वाले विद्यार्थियों की स्थिति और भी चिंताजनक है। उन्हें भीषण गर्मी के इस प्रकोप से बचाने के लिए राज्य सरकारों को गंभीरता से मंथन करना चाहिए। यदि स्कूलों का संचालन जून माह से प्रारंभ किया जाए, तो बच्चों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिल सकती है। वर्तमान समय में पर्यावरणीय असंतुलन का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मानव द्वारा प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के कारण हर वर्ष गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि जो क्षेत्र पहले ठंडे माने जाते थे, वहां भी अब कूलर और एसी की आवश्यकता महसूस होने लगी है। ऐसे में देशभर की राज्य सरकारों को चाहिए कि वे शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल के बजाय 1 जून से करने पर गंभीरता से विचार करें। यह निर्णय न केवल व्यावहारिक होगा, बल्कि बच्चों और शिक्षकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक साबित होगा।

अतः प्रतिवर्ष बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए सरकार को नए शैक्षणिक सत्र के समय में बदलाव पर निर्णय लेना चाहिए और 1 जून से स्कूल खोलने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। यही विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में एक संवेदनशील और दूरदर्शी पहल होगी।

अरविंद रावल

वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर बढ़ती चिंता

टोक्यो में आयोजित एज़ेडईसी-प्लस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विश्वभर में समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि समुद्री रास्ते केवल व्यापार के साधन नहीं हैं बल्कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा हैं और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत का यह रुख उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऐसे में यदि समुद्री मार्गों में किसी भी प्रकार का व्यवधान आता है तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और आम नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। यही कारण है कि भारत ने इस मंच पर सुरक्षित और निर्बाध समुद्री परिवहन को अत्यंत आवश्यक बताया। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि हाल के वर्षों में कई समुद्री क्षेत्रों में तनाव और संघर्ष की स्थितियां बनी हैं, जिनका असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ा है। व्यापारिक जहाजों पर हमले न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हैं बल्कि वे वैश्विक स्थिरता के लिए भी खतरा हैं। एस. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे हमलों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसके खिलाफ कड़े वैश्विक प्रयास जरूरी हैं। ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती पर भी भारत ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। आज के समय में ऊर्जा केवल आर्थिक विकास का आधार नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। यदि ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती है तो इसका प्रभाव उद्योगों, परिवहन और रोजमर्रा के जीवन पर व्यापक रूप से पड़ता है। इस संदर्भ में भारत ने साझेदारी और सहयोग के जरिए ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित और स्थिर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बैठक में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई प्रमुख नेताओं ने भी भाग लिया, जिनमें अनवर इब्राहिम और फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर शामिल थे। इन नेताओं ने भी ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों पर अपने-अपने विचार साझा किए।

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

रेडिको खेतान लिमिटेड यूनिट सीतापुर द्वारा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

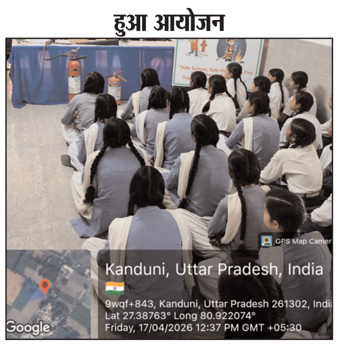

बिसवां/सीतापुर रेडिको खेतान लिमिटेड, यूनिट- सीतापुर द्वारा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस/सप्ताह (14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026)के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्लांट हेड अंशु श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान पास के स्कूल माथुर प्रसाद आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, गाँव-कंदुनि, जनपद सीतापुर में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विवेक वर्मा एवं विशाल शर्मा द्वारा अग्नि सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने आग लगने की स्थिति में बचाव के उपाय, अग्निशमन यंत्रों के उपयोग तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित निकासी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य समाज में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं आपदा के समय सही प्रतिक्रिया के लिए लोगों को तैयार करना था।

आवश्यक सूचना

आधार हाउसिंग की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल शैलेन्द्र कुशवाहा उर्फ शैलेन्द्र पुत्र प्रहलाद उर्फ प्रहलाद कुशवाहा निवासी - ग्राम इटवा उर्फ भरौटा, पोस्ट बैकुंठपुर, देवरिया उ0प्र0- 274501 , अपनी पत्नी श्रीमती गीता देवी पत्नी शैलेन्द्र कुमार कुशवाहा के नाम से भूखण्ड सं0-7 का भाग, जो कि खसरा संख्या- 145 का भाग है जिसका रकबा- 600 वर्गफिट है जो कि स्थित-ग्राम नौबस्ताकलां परगना, तहसील व जिला लखनऊ को ओम प्रकाश पुत्र राम भरोसे से क्रय कर रहे है। जिसकी चौहद्दी पूरब- भूखण्ड संख्या-18 पश्चिम- 28 फिट चौड़ा रास्ता, उत्तर- भूखण्ड सं0-07 का शेष भाग, दक्षिण- भूखण्ड सं0-8 (मनीष सिंह) उपरोक्त भूमि को आधार हाउसिंग फाइनेन्स लि0 में शैलेन्द्र कुशवाहा उर्फ शैलेन्द्र पुत्र प्रहलाद उर्फ प्रहलाद कुशवाहा व श्रीमती गीता देवी पत्नी शैलेन्द्र कुमार कुशवाहा के द्वारा बंधक किया जा रहा है। यदि उक्त खसरे के सह खातेदार श्रीमती पूर्णिमा वर्मा पुत्री जयचन्द, श्रीमती सविता सिंह पत्नी नवीन चन्द, भदौरिया प्रमोटर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रा0लि0 या किसी अन्य व्यक्ति या किसी वित्तीय संस्था या सह खातेदार को उपरोक्त भूखण्ड क्रय-विक्रय या बंधक किये जाने में कोई आपत्ति हो तो इस नोटिस के प्रकाशन तिथि से 7 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करने का कष्ट करें उपरोक्त समयावधि के बाद कोई भी दावा विचार योग्य नही माना जायेगा।

आपत्ति हेतु सम्पर्क करे-
ललित मोहन जोशी एडवोकेट
एमजी-87 अलीगंज, लखनऊ।
डवइपसम.91.9565881290

सूचना

दिल्ली सहकारी ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ग्राउंड फ्लोर, बी-विंग, विकास भवन-II, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054

अपील संख्या: 015/2020
मनोज सिंह
बनाम
सीए सहकारी क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी एवं अन्य
प्रति,
प्रतिवादी संख्या-2 श्री अर्पित सिंह पुत्र श्री राम सहोदर सिंह 820-सी, सेक्टर-3, उद्यान-1, एल्डेको-1, एकता विहार कॉलोनी, लखनऊ (उ.प्र.) पिन-226012 मोबाइल नं.- 9821618655
तथा
प्रतिवादी संख्या-3 श्रीमती इला सिंह पत्नी श्री अर्पित सिंह एवं पुत्री श्री रिपु दमन सिंह सी-15/5, पेपर मिल कॉलोनी, सी-ब्लॉक, अंशिक निशांत गंज (लखनऊ), उ.प्र., पिन-226007 मोबाइल: 090643477/ 7897286123

उपरोक्त मामले के संबंध में प्रतिवादियों संख्या-2 एवं 3 को दिल्ली सहकारी ट्रिब्यूनल, दिल्ली में 21.05.2026 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होने हेतु तलब किया जाता है।

यदि प्रतिवादीगण निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध एक्स-पार्टे (एकपक्षीय) कार्यवाही की जाएगी।

प्रकाशन की सूचना की एक प्रति रिकॉर्ड के लिए इस ट्रिब्यूनल को अवश्य भेज दी जाए।

रजिस्ट्रार
दिल्ली सहकारी ट्रिब्यूनल

देशी लौकिया की गौशाला का वीडियो वायरल, गौ भक्तो में आक्रोश

● वीडियो फोटो शूट करने वालो से लगवाई गयी उठक-बैठक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद-सीतापुर। विकास खण्ड रामपुर मथुरा अंतर्गत एक गौशाला की बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिससे गौभक्तों में भारी रोष व्याप्त है। सोशल मीडिया पर रामपुर मथुरा क्षेत्र की एक गौशाला का हृदय विदारक वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। लोकेशन टैग के साथ वायरल हुए इन दृश्यों ने गौशालाओं के प्रबंधन और पशुओं की सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वायरल वीडियो में गौवंशों की जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसे झुठलाना अब प्रशासन के लिए नामुमकिन है। साक्ष्यों से स्पष्ट है कि सरकारी धन और योजनाओं के बावजूद धरातल पर गौवंश दाने-पानी और उचित देखभाल के अभाव में तड़पने को मजबूर है। यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि बेजुबानों के साथ की गई क्रूरता की पराकाष्ठा है। इसी के साथ एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन लोगों से भी अभद्रता की जा रही जिनके द्वारा इसका वीडियो व फोटो शूट किया जा रहा है। बताया जाता है उनसे उठक बैठक तक भी लगवाई गयी। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और गौशाला संचालकों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। स्थानीय नागरिकों और गौभक्तों का कहना है कि जिम्मेदारों को इस दुर्दशा पर शर्म आनी चाहिए। यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य है।

आक्रोशित लोगों का मानना है कि गौवंशों के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले 'हैवानों' को न केवल कानूनी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि वे ईश्वरीय न्याय से भी नहीं बच पाएं। गौवंशों का श्राप उन सभी को लगेगा जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इन बेजुबानों को मरने के लिए छोड़ दिया।

प्रशासन से जनता की अपील- वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। गौशाला की वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जाएं। दोषियों की पहचान कर उन पर 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' के तहत मुकदमा दर्ज हो। गौसेवा के नाम पर भ्रष्टाचार और क्रूरता करने वालों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

मिशन शक्ति फेज 5 के अन्तर्गत नारी वंदन अधिनियम पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित

चुनार, मीरजापुर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार में उच्च शिक्षा संस्थानों में 10 से 20 अप्रैल 2026 के मध्य 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' प्रचार अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को महाविद्यालय में मिशन शक्ति फेज 5 के द्वितीय चरण में नारी वंदन अधिनियम के समर्थन पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो (डॉ0) माधवी शुक्ला ने किया उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि नारी वंदन अधिनियम के बारे में महिलाओं को विशेष तौर पर बताये जाने की आवश्यकता है। निर्णायक मंडल में प्रो कुसुम लता, डॉ मंजूला शुक्ला एवं डॉ अदिति सिंह रही। प्रतियोगिता में जान्हवी मोदनवाल एम ए प्रथम वर्ष,पायल गुप्ता बी ए सी प्रथम वर्ष,अंशिका मोदनवाल बीए द्वितीय वर्ष ने क्रमशः प्रथम द्वितीय, एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। सान्तवना प्राची सिंह बीए सी प्रथम वर्ष ने प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन मिशन शक्ति प्रभारी डॉ शेफालिका राय के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर कुल 43 छात्र- छात्राएँ सहित, डपारस सिंह, क़ुर्बान एवं प्रमिला देवी उपस्थित रहे।

सीबीएसई हाईस्कूल में न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल का शत प्रतिशत परिणाम

● 96.8 प्रतिशत अंक राजवीर रहे विद्यालय के टॉपर।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के सुरेंद्र सरस्वती नगर स्थित न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल का सीबीएसई बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा। विद्यालय के राजवीर सिंह ने 96.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। राजीव दीक्षित 96.60 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहे। शिवांश सिंह, शक्ति वर्धन सिंह और सूर्यांशी सिंह ने 96.20 प्रतिशत अंक पाकर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। निहारिका त्रिवेदी ने 96 प्रतिशत अंक हासिल कर चौथा स्थान पाया।

शशांक त्रिपाठी 95.80 प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर रहे। राघव मिश्रा ने 95.60 प्रतिशत अंक पाकर छठा स्थान प्राप्त किया। सुवर्णा तिवारी और यशस्वी ने 95.40 प्रतिशत अंक पाकर सातवां स्थान हासिल किया। अवनीश त्रिपाठी 95 प्रतिशत के साथ आठवें स्थान पर रहे। प्रीति गौतम ने 94.60 प्रतिशत अंक पाकर नौवां स्थान प्राप्त किया। छात्रा दिशा जैन, अक्षय सोनी और मयंक भूषण ने 94 प्रतिशत अंक प्राप्त कर दसवां स्थान हासिल किया।विद्यालय प्रबंधक डॉ. शशिकांत शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवांग अवस्थी ने छात्र-छात्राओं की उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की है।

जनपद न्यायाधीश ने राजकीय सम्प्रेक्षण गृह व बालिका आश्रय गृह का किया औचक निरीक्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली:- जुवेनाइल जस्टिम कमेटी के अध्यक्ष मा0 न्यायमूर्ति अजय भनोट के द्वारा किशोर अपराधियों द्वारा मादक पदार्थो के सेवन के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के अनुपालन में मा0 जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अध्यक्षता में समिति के द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह व बालिका आश्रय गृह, रायबरेली का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिशा, मुख्य विकास अधिकारी अंजूलता, जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा, बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह, जिला क्रीड़ाधिकारी व जिला उद्यान अधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान जिला जज द्वारा आवासित किशोर अपराधियों से मादक पदार्थों के सेवन के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त जिला जज द्वारा आवासित किशोर के खानपान, रहन-सहन, पढ़ाई, खेलकूद व व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये। इसके अतिरिक्त बालिका गृह रायबरेली का भी निरीक्षण किया गया। आवासित बालिकाओं को भी मादक पदार्थों व नशीली दवाओं के इस्तेमाल से होने वाली शारीरिक समस्याओं के बाबत अवगत कराते हुए इनका इस्तेमाल न करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। परिसर में खेलकूद हेतु बने बैड़मिटन कोर्ट सही न पाये जाने पर प्रबन्धक गाँधी सेवा निकेतन को मुख्य विकास अधिकारी से सहयोग लेते हुए सही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

निरीक्षण के उपरांत राजकीय सम्प्रेक्षण गृह रायबरेली में आवासित किशोर अपराधियों के विधिक अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता का आयोजन किया गया। उक्त जागरुकता शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिशा के द्वारा बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त बच्चों हेतु स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। इस शिविर में अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह रन बहादुर वर्मा, डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिंल जय सिंह यादव व पराविधिक स्वयं सेवक पवन कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में लगी आग 6 घंटे के बाद भी आग पर नहीं पाया गया काबू

आग बुझाने में ड्रमंडगंज वन रेंज की टीम लगी रही लेकिन आग अपनी स्पीड से दौड़ती रही

हलिया, मीरजापुर। ड्रमंडगंज वन रेंज के महुगढ़ी जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों मे आग लग गई लगभग 1:00 बजे से लेकर 6:00 तक आग दूदू कर जलती रही काफी देर से पहुंची वन विभाग की टीम आग बुझाने का प्रयास करती रही लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया 6 घंटे तक आग अपनी स्पीड से दौड़ती रही। स्थानिय ग्रामीणों ने बताया कि हर वर्ष जंगल में इसी तरीके से आग लग जाता है आग का कोई पता नहीं चलता कि कैसे लगी आग यहां तक की लोगों ने वन विभाग की संदिग्ध भी बताएं कि हर वर्ष आग लगने का नहीं चला पता खबर लिखे जाने तक आग पर नहीं पाया गया था काबू महुगढ़ी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान सुरेश केसरी ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि पहाड़ के नीचे ही बनाया गया है गौशाला हम लोग गौशाला की सुरक्षा करने में लग रहे की आग की लपट से पशुओं को ना हो तकलीफ।

एस.एम.एस. ऑफ इंस्टीट्युशन्स के संस्थापक स्व. सतीश कुमार सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के एस.एम.एस. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के संस्थापक स्वर्गीय सतीश कुमार सिंह की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अत्यंत श्रद्धा एवं भावपूर्ण वातावरण में किया गया। इस अवसर पर संस्थान के शैक्षणिक, गैरशैक्षणिक, उच्च अधिकारियों एवं छात्रों ने स्व. सतीश कुमार सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व को स्मरण किया। वक्ताओं ने कहा कि वे केवल एक कुशल प्रशासक ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी चिंतक, वैज्ञानिक, दृष्टिकोण से युक्त तथा गहन आध्यात्मिक सोच के धनी व्यक्तित्व थे। उन्होंने फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर के पद से सेवा निवृत्त होकर अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य किए। सन् 1995 में जब प्रदेश में मात्र कुछ ही संस्थान उच्च शिक्षा हेतु उपलब्ध थे तब स्व. सतीश कुमार सिंह के अथक प्रयास, प्रेरणा एवं छात्रों को उच्च शिक्षा सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य हेतु स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साईसेज (एस.एम.एस.) वाराणसी परिसर की स्थापना की गयी, इसी क्रम में सन् 2008 में लखनऊ परिसर स्थापित हुआ। एस.एम.एस. वाराणसी परिसर में सन् 2002 में स्थापित सेन्टर फार स्प्रीचुलिज्म एण्ड ह्यूमन इनरिचमेंट के साथ लखनऊ परिसर में स्थापित सर सी.वी.रमन रिसर्च सेन्टर एवं वैदिक विज्ञान केंद्र उनकी दूरदर्शी सोच और ज्ञान- समर्पित दृष्टिकोण के जीवंत उदाहरण हैं, जो आज भी विद्यार्थियों एवं समाज को प्रेरित कर रहे हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से संस्थान परिसर में हर्बल एवं औषधीय पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण के अवसर पर संस्थान के सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद सिंह ने संस्थान के संस्थापक स्व. सतीश कुमार सिंह को याद करते हुए कहा कि संस्थान संस्थापक महोदय की प्रेरणा के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के प्रति सदैव कटिबद्ध रहेगा। इस अवसर पर संस्थान प्रांगण में एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभाग किया। कार्यक्रम के दौरान डॉ. भरत राज सिंह, महानिदेशक (तकनीकी), एसएमएस लखनऊ द्वारा लिखित एवं स्व. सतीश कुमार सिंह को समर्पित पुस्तक ''सुपर ब्रेनः योग और ध्यान'' का विधिवत विमोचन किया गया। इस पुस्तक में योग एवं ध्यान के माध्यम से मानसिक सशक्तीकरण और जीवन में संतुलन स्थापित करने के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर आशियाना स्थित कुष्ठ रोगियों के आश्रम में रह रहे कुष्ठ रोगियों को भोजन के पैकेट का वितरण भी किया गया। संस्थान के निदेशक डॉ. आशीष भटनागर, महानिदेशक (तकनीकी) प्रो. (डॉ.) भरत राज सिंह, निदेशक (प्रशासन) डॉ. जगदीश सिंह, एसोसियेट डायरेक्ट डॉ. धर्मेन्द्र सिंह, अधिष्ठाता डॉ. पी. के. सिंह, रजिस्ट्रार शेष नारायण शुक्ला, मुख्य महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के साथ सभी संकायाध्यक्षों, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों ने स्व. सतीश कुमार सिंह को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि प्रदान की।

महमूदाबाद में छात्र संसद शपथ समारोह आयोजित, विद्यार्थियों में नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना पर जोर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद-सीतापुर आत्मविश्वास और रचनात्मकता का विकास हमारी सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं से होता है। वाद-विवाद, भाषण, त्वरित भाषण और अंत्याक्षरी जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। विद्यार्थियों को अनुशासित रहकर पूरे मनोयोग से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।

यह बातें सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आरके वाजपेयी 'विरल' ने शुक्रवार को कालेज के शास्त्री सभागार में आयोजित छात्र संसद शपथ ग्रहण समारोह में नव नियुक्त पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के बाद कहीं। उन्होंने कहा कि छात्र संसद से बच्चों में नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी का भाव विकसित होता है। ऐसे कार्यक्रमों से हमारी सांस्कृतिक परंपराएं जीवित रहती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। छात्र संसद के तहत सांस्कृतिक विभाग में श्रेया रॉय को अध्यक्ष, अभिनव अवस्थी को उपाध्यक्ष, आदित्य प्रजापति को महामंत्री, अशिंका यादव को मंत्री, रिज़ा फातिमा को मुख्य प्रवक्ता, कोमल यादव को प्रवक्ता और प्रतिक्षा राज को कोषाध्यक्ष बनाया गया। सदस्य के रूप में निशा जायसवाल, अभय प्रताप सिंह और दिया राय शामिल रहीं। वहीं शिशु भारती विभाग में द्विव्यांश यादव को अध्यक्ष, उज्ज्वल वर्मा को उपाध्यक्ष, रिचा को महामंत्री, आर्यन कश्यप को मंत्री, अशिंका मिश्रा को मुख्य प्रवक्ता, तनु सिंह को प्रवक्ता तथा इशिका गुप्ता और सौम्या श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सदस्य के रूप में अभिनव वर्मा और सौम्या श्रीवास्तव को भी शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 11 के छात्र उज्ज्वल वर्मा ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन सांस्कृतिक प्रमुख प्रतिभा सिंह ने किया। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य यशपाल वर्मा, व्यवस्था प्रमुख शिवसेवक मिश्र, अखिलेश शर्मा, अजय सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

एल्पिस ग्लोबल स्कूल में मेधावी विद्यार्थियों का हुआ अलंकरण, विद्यालय परिसर में गूंजा उत्साह और गर्व

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां सीतापुर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की नई मिसाल कायम करते हुए एल्पिस ग्लोबल स्कूल बिसवां ने इस वर्ष भी शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम देकर इतिहास रच दिया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में विद्यालय में एक भव्य अलंकरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसने पूरे कार्यक्रम को विशेष बना दिया। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित किया गया। आस्था (97.6%), शौर्य वर्मा (97%), कृष्णा सिंह (96.4%), अभिनव पटेल (96.4%), अविका गुप्ता (96.2%), रुश्दा फुरकान (96.2%) सहित अनेक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन के श्री मुदित सिंघल एवं श्री उमंग राजवंशी ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उनके संबोधन ने समारोह को भावुक और प्रेरणादायक बना दिया।

विद्यालय की प्राचार्या दीपा चंद्रा ने विद्यार्थियों की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का संयुक्त परिणाम है। इस अवसर पर उपस्थित अभिभावकों ने विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन एवं उत्कृष्ट व्यवस्था की सराहना की। पूरे समारोह के दौरान विद्यालय परिसर में खुशी, गर्व और उत्साह का माहौल बना रहा। एल्पिस ग्लोबल स्कूल का यह परिणाम और भव्य सम्मान समारोह एक बार फिर यह संदेश देता है कि सही मार्गदर्शन, अनुशासन और परिश्रम से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

रेलवे पटरी के निकट अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी

बिसवां, सीतापुर कोतवाली बिसवां क्षेत्र के ग्राम सरैया माफी में रेलवे पटरी के निकट अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यह स्थान रॉयल भट्ठे के उत्तर दिशा में स्थित है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक राम राघव सिंह ने बताया कि शव लगभग दो-तीन दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। आसपास के लोगों के अनुसार मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों की जानकारी हो सकेगी। फिलहाल पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पूर्व मंत्री के पेट्रोल पंप पर साइबर ठगी, एकाउंट हुआ फ्रीज

● गूगल पे व फोन पे आदि जैसे ऑनलाइन लेन-देन के माध्यम अब हुए जोखिम भरे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद-सीतापुर नगर के एक पेट्रोल पंप पर साइबर ठग द्वारा खाते में पैसे भेजकर सीएनजी भरवाई और शिकायत करके पेट्रोल पंप का खाता भी फ्रीज करवा दिया। ऐसा ही एक मामला महमूदाबाद कस्बे के पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रहा हैं, बताया जा रहा है कि कई पेट्रोल पम्पों के लाखों रुपए ब्लॉक किये जा चुके है।

आज एक ताजा मामला सामने आया है। नगर के साई पेट्रोल पम्प, स्थित पैतेपुर रोड निकट मोतीपुर चौराहा का पूरा बैंक एकाउंट फ्रीज (बंद) किया गया, तब हड़कंप मच गया, छानबीन करने पर जब सारी सच्चाई मालूम पड़ी तो वहाँ के मैनेजर द्वारा स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया गया। यह पंप पूर्व विधायक व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा का है इसकी शिकायत उन्होंने जिले के पुलिस कप्तान से भी मिलकर की है। बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध व्यक्ति अपने वाहन में कई बार सीएनजी डलवाई और UPI के माध्यम से आनलाइन पैसा डाला, आज वह व्यक्ति फिर सीएनजी डलवाने गया तब सेल्समैन ने उसे पहचान कर उससे पूंछतांछ करने लगे, तो वह गाड़ी छोड़ कर भाग गया। इस पेट्रोल पंप के लगभग तीन लाख से ऊपर की रकम की शिकायत है। पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल ले लिया या फिर सेल्समैन से साठगांठ कर नगद ले लिया, फिलहाल जांच जारी है।

लखनऊ में चला प्रशासन का बुलडोजर, एक ही दिन में 7.75 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया कब्जा

सरोजनीनगर (लखनऊ)। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को सरोजनीनगर तहसील क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने जेसीबी चलाकर दो गांवों से कुल 7 करोड़ 75 लाख रुपये बाजार कीमत की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई। नायब तहसीलदार तेजस्वी प्रकाश के नेतृत्व में ग्राम औरंगाबाद जागीर में खसरा संख्या 803, 805, 843, 1145 व 1146 की 0.557 हेक्टेयर जमीन पर बनी रेडीमेड बाउंड्रीवॉल, दुकानें व टीनशेड ध्वस्त कर 7.25 करोड़ की भूमि खाली कराई गई। इसके साथ ही ग्राम अशरफ नगर में अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव व एसडीएम अंकित शुक्ला के निर्देशन में खसरा संख्या 734/1 की 0.253 हेक्टेयर रास्ते की जमीन पर अवैध रूप से खड़ी बाउंड्रीवॉल तोड़कर 50 लाख की पांच सौ वर्गमीटर जमीन मुक्त कराई गई। नायब तहसीलदार नगर निगम तेजस्वी प्रकाश ने बताया कि कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों में विरोध भी किया लेकिन बावजूद इसके दोनों जगह कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण रही।

चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 99वीं जयंती

● सीतापुर 17 अप्रैल चन्द्र भानु गुप्त कृषि महाविद्यालय में

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की 99 वीं जयंती मनाई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ वाई के सिंह एवं प्रशासनिक अधिकारी शिवमंगल चौरसिया ने चंद्रशेखर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया । डॉ योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चंद्रशेखर जी दृढ़ इच्छाशक्ति, सिद्धांतों के प्रति अडिग और निर्भीक जननेता के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त किया। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चंद्रशेखर जी के नाम पर महाविद्यालय में कृषि फार्म है जिसमें परास्नातक कृषि के छात्र-छात्राएं शोध करते हैं जिनका सीधा लाभ किसानों को मिलता है।

उनकी स्मृति हम सभी को निरंतर कर्तव्यनिष्ठा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेंगी। इस अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉ हृदय नारायण तिवारी, डॉ विवेक कुमार वर्मा, डॉ श्वेता मिश्रा, डॉ उपमा त्रिपाठी, डॉ राजीव कृष्ण बाजपेई, डॉ पी के मिश्रा डॉ पी के सिंह, डॉ अनिल कुमार वर्मा, डॉ आशुतोष, डॉ विवेक कुमार वर्मा, डॉ पुष्पा यादव, डॉ नलिनी मिश्रा, डॉ दीप्ति श्रीवास्तव, डॉ रजनी शुक्ला, डॉ सुधाकर सिंह, विपुल अग्रवाल, डॉ धर्मेश कुमार सिंह, प्रेम बाबू चौरसिया, डॉ रवी शंकर वर्मा, जितेंद्र बाजपेई, रामप्रकाश, सत्रोहन एवं संतपाल यादव सहित सभी शिक्षक और कर्मचारीयों चंद्रशेखर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित श्रद्धांजलि दी।

संक्षिप्त खबरें

जिले की दुल्लभछड़ा-बदरपुर रेल सेवा यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे विभाग ने फिर से शुरू की, यात्रियों को राहत

मीडिया और जागरूक नागरिकों की सक्रिय भूमिका की स्थानीय लोगों ने सराहना की।

श्रीभूमि: श्रीभूमि जिले में लंबे समय से बंद दुल्लभछड़ा-बदरपुर (ट्रेन संख्या 55689) लोकल रेल सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण मार्ग पर सेवा बंद होने के कारण पिछले कुछ दिनों से यात्रियों में भारी असंतोष और गंभीर असुविधा देखी जा रही थी। इस मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों कर्मचारी, छात्र और व्यापारी यात्रा करते हैं। ऐसे में ट्रेन सेवा अचानक बंद हो जाने से स्थानीय जनजीवन पर बड़ा असर पड़ा और वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया था। इस मामले को लेकर मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद और जागरूक नागरिकों की सक्रिय पहल पर रेलवे अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इसके बाद सेवा को 17 अप्रैल शुक्रवार को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया। रेलवे विभाग के अनुसार, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर सेवा को फिर से सामान्य कर दिया गया है। साथ ही इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए मीडिया और स्थानीय नागरिकों के प्रति क्षेत्र की ओर से आभार भी व्यक्त किया गया है। सेवा बहाल होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है और समस्या का शीघ्र समाधान होने पर संतोष व्यक्त किया है।

ईरान जंग की सबसे बड़ी खबर, 49 दिन बाद पूरी तरह खोला गया होर्मुज स्ट्रेट

ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने शुक्रवार को घोषणा की कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सभी कमर्शियल जहाज़ों के गुज़रने का रास्ता, सीज़फ़ायर की बाकी अवधि के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जलडमरूमध्य से जहाज़ों का गुज़रना उसी तय रास्ते से होगा, जिसकी घोषणा ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन ने पहले ही कर दी थी। एक्स पर एक बयान में उन्होंने कहा कि लेबनान में सीज़फ़ायर के मद्देनज़र, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सभी कमर्शियल जहाज़ों के गुज़रने का रास्ता, सीज़फ़ायर की बाकी अवधि के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है; यह उसी तय रास्ते से होगा, जिसकी घोषणा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन ने पहले ही कर दी थी। इससे पहले, अमेरिका ने कहा था कि वह होर्मुज़ जलडमरूमध्य की नौसैनिक नाकेबंदी शुरू करेगा; यह कदम तब उठाया गया, जब ईरान ने फ़रवरी में अपने ऊपर हुए अमेरिका-इज़रायल हमले के जवाब में, दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग मार्ग को हफ़्तों तक प्रभावी रूप से बंद रखा था।

ऑटो चालक की घिनौनी हरकत, MMS बनाकर धमकी- पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंबई के कुरार इलाके से एक बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक ऑटो रिक्शा चालक ने महिला यात्री का छिपकर वीडियो (MMS) बनाकर उसे ब्लैकमेल करने और जबरन संबंध बनाने की कोशिश की।

क्या है पूरा मामला? पुलिस के अनुसार, पीड़ित लड़की कुरार से मालाड स्थित चस्नष्ट जाने के लिए ऑटो लेने वाली थी। तभी आरोपी ऑटो चालक मोहम्मद अफजल आशिफ खान ने उसे अपने ऑटो में बैठाया और सफर के दौरान अपने मोबाइल से चुपके से उसका वीडियो बनाने लगा। लड़की को शक हुआ, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। जब वह KFC पहुंची और पैसे देने लगी, तब भी आरोपी वीडियो बनाता रहा। विरोध करने पर आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और जबरन संबंध बनाने की कोशिश की।

ट्रैफिक पुलिस का तुरंत एक्शन घटना के वक्त मौके पर मौजूद समता नगर ट्रैफिक पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया और उसे कुरार पुलिस के हवाले कर दिया। **पुलिस का बयान** कुरार पुलिस के अधिकारी उमेश पाटील के मुताबिक, पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, बिना अनुमति वीडियो बनाने और धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। **क्या-क्या आरोप लगे?** आरोपी पर निम्न आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया है: महिला से छेड़छाड़, बिना इजाजत वीडियो बनाना, ब्लैकमेल और धमकी देना जबरन संबंध बनाने का प्रयास **आगे की कार्रवाई** फिलहाल कुरार पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने पहले भी ऐसी वारदातें की हैं या नहीं।

पुतिन दिल्ली आ रहे, एक से बढ़कर एक हथियारों के साथ S-500 भी ला रहे हैं! चीन-पाक में हड़कंप

● एस 500 आखिर इतना खतरनाक क्यों है और पाकिस्तान और कई दुश्मन देश इससे डरते क्यों हैं? इसकी रेंज जो है S500 की ये 600 किमी है।

एस 400 की 400 कि.मी. रिस्पांस टाइम S500 का 3 से 4 सेकंड है और S400 का करीब 10 सेकंड। हाइट कैपेबिलिटी की बात करें तो S500 200 कि.मी. स्पेस तक और एस 500 300 कि.मी. ट्रैकिंग पावर।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार दूसरे साल भारत आने वाले हैं। बता दें कि पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मचा दी है। लेकिन कहानी सिर्फ यहां पर बता दें कि पुतिन के दौरे की नहीं है। कहानी उस खतरनाक डिफेंस डील की है जो भारत की ताकत को बता दें कि कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। दरअसल इस साल भारत में होने जा रहा है ब्रिक्स समिट 2026 जहां पुतिन का आना लगभग तय माना जा रहा है और बता दें कि खास बात इस दौरे की यह है कि पुतिन इससे पहले दिसंबर 2025 में भी भारत आ चुके हैं। यानी लगातार दूसरे साल पुतिन का भारत दौरा है और यह दिखाता है कि इंडिया रशिया पार्टनरशिप कितनी मजबूत हो चुकी है। लेकिन असली धमाका यहां पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अब भारत को सिर्फएस 500 ही नहीं बल्कि उससे कई गुना ज्यादा एडवांसएस 500 एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है और इतना ही नहीं रूस ये भी चाहता है कि भारत के साथ मिलकर एस 500 का जॉइंट प्रोडक्शन भी शुरू किया जाए।

एस 500 आखिर इतना खतरनाक क्यों है और पाकिस्तान और कई दुश्मन देश इससे डरते क्यों हैं? इसकी रेंज जो है स500 की ये 600 किमी है।

एस 400 की 400 कि.मी. रिस्पांस टाइम स500 का 3 से 4 सेकंड है और S400 का करीब 10 सेकंड। हाइट कैपेबिलिटी की बात करें तो S500 200 कि.मी. स्पेस तक और एस 500 300 कि.मी. ट्रैकिंग पावर। ट्रैकिंग पावर की बात करें तो एस 500 100 टारगेट और एस 400 80 टारगेट। कैपेबिलिटी की बात करें तो एस 500हाइपरसोनिक बैलस्टिक मिसाइल और स्पेस टारगेट तक मार कर सकता है। और एस 400 की बात करें तो एयरक्राफ्ट ड्रोन क्रूज मिसाइल तक सीमित है। यानी यह साफ है कि S500 एक गेम चेंजर है।

अगर यह डील मेक इन इंडिया के तहत होती है तो भारत दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाले देशों में भी शामिल हो जाएगा। और इससे क्या होगा? अब आप उसे भी समझ लीजिए। भारत की सुरक्षा कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दुश्मनों के लिए डिट्रेस बढ़ेगा और ग्लोबल डिफेंस पावर में इंडिया की जो पोजीशन है वो कई गुना ज्यादा ऊपर चली जाएगी। पुतिन का लगातार भारत आना यह भी साफ दिखाता है कि रूस आज भी भारत को अपना सबसे ज्यादा भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है और ब्रिक्स जैसे मंच पर भारत की ग्लोबल लीडरशिप और भी ज्यादा मजबूत होती हुई भी इससे नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो पुतिन का भारत दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है। ये एक ऐसा संकेत है कि भारत अब सिर्फ फॉलोअ नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बन रहा है।

श्रीभूमि जिला के जयनगर गांव की सड़क की हालत जर्जर, ग्रामीणों को भारी परेशानी

● **विभागीय अधिकारी से हस्तक्षेप की मांग।**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि : श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दुल्लभछड़ा के निकट कालाछड़ा क्षेत्र से जयनगर, तारापुर और बालिया सहित कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को लंबे समय से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस जर्जर सड़क के कारण आम जनता, छात्र-छात्राएं, मरीज और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है। विशेषकर बरसात के मौसम में सड़क की हालत और अधिक खराब हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क कई स्थानों पर कच्ची, टूटी-फूटी और पूरी तरह से अनुपयोगी हो चुकी है। ऐसे में आपातकालीन सेवाओं, जैसे एंबुलेंस और अन्य वाहनों का संचालन भी लगभग असंभव हो जाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वर्षों से इस मार्ग की मरम्मत या पक्कीकरण नहीं किया गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने संबंधित विभाग से इस महत्वपूर्ण सड़क के शीघ्र मरम्मत एवं पक्कीकरण की मांग की है और प्रशासन से इस दिशा में त्वरित एवं ठोस कार्रवाई की अपील की है।

श्रीभूमि जिले के दरगारबंद जीपी के कामुमाई छड़ा क्षेत्र में सड़क की जर्जर हालत

● **ग्रामीणों ने खुद शुरू की मरम्मत प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग।**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाने के दावों के बावजूद, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़क निर्माण का लंबे समय से किया गया आश्वासन अब तक पूरा नहीं होने से श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के दुल्लभछड़ा के निकट दरगारबंद जीपी के 3 नंबर वार्ड के निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कामुमाई छड़ा के पश्चिमी किनारे से गुजरने वाली यह ग्रामीण सड़क कई वर्षों से उपेक्षित अवस्था में है। शुष्क मौसम समाप्त हो जाने के बावजूद आज तक यहां एक भी कोदा मिट्टी का कार्य नहीं किया गया है।

स्थिति से मजबूर होकर दरगारबंद जीपी के 1 नंबर वार्ड के निवासी कमला कांत यादव, रंजीत लोहार, विजय यादव और राज कुमार मिश्रा ने अपने निजी खर्च पर कई ट्रक मिट्टी और ईंट लाकर सड़क को किसी तरह चलने योग्य बनाने का प्रयास किया है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के अनुसार ब्रजकृष्ण सिंह के घर के सामने से दरगारबंद जीपी के 6 नंबर वार्ड के दक्षिण छनटिला दुर्गा मंदिर तक PMGSY के तहत सड़क निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, लेकिन वह अब तक धरातल पर नहीं उतर सका है और फाइलों में ही लंबित है। कई बार आवेदन और ज्ञापन देने के बावजूद कोई समाधान न मिलने पर ग्रामीण स्वयं ही अस्थायी रूप से सड़क की मरम्मत करने को मजबूर हैं। इसी बीच कामुमाई छड़ा पर पुल निर्माण के लिए दो स्थानों पर बड़े अस्थायी बांध बनाए जाने से जलप्रवाह बाधित हो गया है, जिससे दोनों किनारों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे छोटे वाहनों, विशेषकर ऑटो रिक्शा का संचालन अत्यंत जोखिमपूर्ण हो गया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले लगभग तीन महीनों से छड़ा का पानी रुका हुआ है, जिसके कारण यह अब मवेशियों के पीने योग्य भी नहीं रहा है और क्षेत्र में विभिन्न बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द स्थायी सड़क और पुल निर्माण के साथ जलप्रवाह सामान्य करने हेतु प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

दिल्ली में रिटायर्ड इंजीनियर से ठगे 2.7 करोड़ रुपये, बेटी के भविष्य के लिए बचाई रकम गंवाई

पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में कृष्णा नगर निवासी 77 वर्षीय रिटायर्ड ऑटो इंजीनियर एक सुनियोजित ऑनलाइन निवेश ठगी का शिकार हो गए। आरोप है कि फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें ऊंचे मुनाफे का लालच देकर करीब 2.7 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले उनके मोबाइल पर एक वॉट्सऐप मैसेज आया, जिसके बाद उन्हें एक ग्रुप में जोड़ लिया गया। इस ग्रुप में करीब 100 से अधिक सदस्य थे और रोजाना शेयर बाजार से जुड़े टिप्स, निवेश के सुझाव और भारी मुनाफे के स्क्रीन-शॉट साझा किए जाते थे। ग्रुप को संचालित करने वाला व्यक्ति खुद को एक नामी ट्रेडिंग कंपनी का डायरेक्टर बताता था और निवेशकों को भरोसा दिलाता था कि उनके जरिए निवेश करने पर कम समय में बड़ा फायदा होगा। धीरे-धीरे पीड़ित को एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर निवेश करने के लिए कहा गया। यह ऐप बिल्कुल असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसा दिखता था। शुरुआत में छोटे-छोटे मुनाफे दिखाकर उनका भरोसा जीता गया। इसके बाद उन्होंने अपने और पत्नी के बैंक खातों से बड़ी रकम निवेश करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में ऐप में उनका पोर्टफोलियो 8 करोड़ रुपये से अधिक दिखने लगा, जिससे वे और ज्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित हुए। मार्च के शुरुआती दिनों में उन्हें एक कंपनी में बड़े निवेश का ऑफर दिया गया, जिसमें लाखों शेयर आवंटित होने की बात कही गई। पीड़ित ने इस पर भरोसा कर और रकम डाल दी। लेकिन जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की तो हर बार तकनीकी दिक्कत या अन्य कारण बताकर टाल दिया गया। लगातार प्रयास के बावजूद जब कोई पैसा वापस नहीं मिला, तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ।

तेल, गैस...भारत का दिल देखो, मुसीबत में एक नहीं अनेक देशों को कर रहा मदद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पूरी दुनिया के सामने ऊर्जा संकट है। यूरोप से लेकर अफ्रीका और अफ्रीका से लेकर एशियाई देश हर कोई ऊर्जा संकट के लिए परेशान है। वजह साफ है अमेरिका ईरान जंग के कारण स्टेट ऑफ हार्मोस बंद और फिर इससे पूरे दुनिया के ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर। ऐसे में भारत के पड़ोसी देश मुसीबत में हैं तो क्या भारत इनका साथ छोड़ देगा? जवाब है नहीं। यही जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय से सामने आई है। बात भूटान की हो, नेपाल की हो, श्रीलंका की हो, मॉरिसिस की हो, हर जगह भारत ने उनकी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है। पड़ोसी कई एक पड़ोसी मुल्क से हमारे पास उनकी तरफ से अनुरोध आया है कि हम उनको ऊर्जा सामग्री उनको उपलब्ध कराएं। कई एक देशों को भारत ऊर्जा सामग्री उपलब्ध करा रहा है। लेकिन इस दरमियान भारत की अपनी जरूरतें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए और किस प्रकार की यहां पर उपलब्धि है उसको मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश को 22,000 मेट्रिक टन हाई स्पीड डीज़ल मार्च के महीने में मुहैया कराया था और साथ ही साथ इस महीने भी हमारे जो उनको ऊर्जा सामग्री और डीजल दी जाती है वह भी उनको दिया जा रहा है। श्रीलंका के संदर्भ में आपको पता है कि 38,000 मेट्रिक टन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत ने पिछले महीने उनको भेजा था। एक सप्ताह पहले हमारे विदेश मंत्री मॉरिशस के दौरे पर गए थे। उस दौरान दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई इस मुद्दे पर और अभी हम लोग इस प्रक्रिया में हैं कि दोनों देशों के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के स्तर पर एक एग्रीमेंट को रूप फाइनल रूप देने की प्रयास कर रहे हैं ताकि मॉरिशस की जो ऊर्जा स्थिति है वह बेहतर हो और भारत उनको ऑयल और गैस प्रदान करें। जहां तक नेपाल का सवाल है, नेपाल और भारत के बीच जो पहले से चल रहे जो जो एग्रीमेंट हैं, एक तो एग्रीमेंट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल के बीच में है जिसके तहत हम उनको पेट्रोलियम पदार्थ उसको उनको उपलब्ध कराते हैं। और यह उनकी जरूरतों के मुताबिक उनको मुहैया कराया जा रहा है।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि बिना कोई

इंटरप्शन के, बिना कोई बाधा के उनको दिया जा रहा है। उसी तरह भूटान के साथ भी हमारे दोनों देशों के बीच में एक समझ है, एक साझेदारी है। ऊर्जा पदार्थ को लेके उनको भी ऊर्जा हम मुहैया करा रहे हैं। जहां तक मालदीव और सेशल्स की बात है, उनसे भी कुछ हमारे पास अनुरोध आया है और अह उनसे उनसे हमारी लगातार इस मामले में बातचीत चल रही है। मैं साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे पड़ोसी देशों की तरफ से उनके सरकार की तरफ से उन्होंने इस बात की सराहना की है कि हम लोग भारत की तरफ से उनको ऊर्जा सामग्री उनको इस दौरान जब पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहा है इस दरमियान उनको मुहैया कराया जा रहा है।

200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलीन फर्नांडिस ने सरकारी गवाह बनने की दी अर्जी, ईडी से मांगा जवाब

● जैकलीन ने 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग में सरकारी गवाह बनने की अर्जी दी।

● पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा, अगली सुनवाई 20 अप्रैल।

● मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा, जैकलीन पहले आरोपी थीं।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने खुद को सरकारी गवाह बनाने की मांग करते हुए याचिका दायर की। अदालत ने इस पर ईडी से जवाब मांगा है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए तय की है। मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जिस पर 200 करोड़ रुपये की ठगी और उससे जुड़े धन के मनी लांड्रिंग का आरोप है। जांच के दौरान ईडी ने जैकलीन को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था और बाद में पूरक आरोपपत्र में उन्हें पहली बार आरोपित बनाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

इससे पहले, पिछले वर्ष तीन जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज ईसीआइआर को रद करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिससे उनके खिलाफ जांच जारी रही। मूल मामला दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर्स शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी की।

चंद्रशेखर और उसकी पत्नी के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई

जांच एजेंसियों के अनुसार, चंद्रशेखर और उनकी पत्नी अभिनेत्री लीना पालोज ने हवाला नेटवर्क और शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर अपराध से अर्जित धन को छिपाने और इधर-उधर करने का काम किया। दोनों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इस मामले में मकोका के तहत भी कार्रवाई की गई।

दिल्ली के वसंत एन्क्लेव में ब्रिगेडियर और उनके बेटे के साथ मारपीट मामले में चार और आरोपी गिरफ्तार

दक्षिणी दिल्ली। वसंत एन्क्लेव में ब्रिगेडियर और उनके बेटे से मारपीट मामले में पुलिस ने चार और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित घटना को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहे थे। गिरफ्तार आरोपितों में मेहरम नगर निवासी सुरजीत सिंह, सुनील शर्मा एवं आशीष और भिवानी (हरियाणा) निवासी सतेंद्र शामिल हैं। सुरजीत, मुख्य आरोपित सतेंद्र का परिचित है। ये सभी मेहरम नगर में एक साथ बैठे थे, तभी सतेंद्र का फोन आया जिसमें उसने वसंत एन्क्लेव में हुए झगड़े के बारे में बताया।

घटना के बाद से सभी फरार थे

इसके बाद सभी सुरजीत की कार (हुंडई और, सफेद रंग) से घटनास्थल पर गए। वहां पहुंचने पर झगड़ा हुआ और फिर वे अपने-अपने घर लौट आए। बाद में जब उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, तो वे अपने घरों से फरार हो गए। मामले की जांच की जा रही है।

संघर्ष, सेवा और सफलता की प्रेरक कहानी वकालत के साथ समाज सेवा का संगम: अधिवक्ता रवि भूषण चौबे की अनोखी पहचान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए यह विचार अधिवक्ता रवि भूषण चौबे के जीवन का मूल आधार है। यही सोच उनके व्यक्तित्व उनके पेशे और उनके सामाजिक कार्यों में स्पष्ट रूप से झलकती है अधिवक्ता रवि भूषण चौबे का जीवन इस सत्य का सशक्त उदाहरण है कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प निरंतर परिश्रम और समाज के प्रति समर्पण की भावना हो तो वह किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। बिहार के बक्सर जिले की साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली तक और वहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाना उनके अदम्य साहस और अथक संघर्ष की प्रेरक गाथा है वर्ष 1994 में Vinoba Bhave University से अर्थशास्त्र ऑनर्स की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली का रुख किया और niversity of Delhi में एम.ए. में प्रवेश लिया अध्ययन के दौरान उनकी गहरी रुचि पत्रकारिता में भी विकसित हुई जिसने उन्हें समाज के जमीनी सच और आमजन की समस्याओं को नजदीक से समझने का अवसर प्रदान किया यही अनुभव आगे चलकर उनके व्यक्तित्व को संवेदनशील जागरूक और जनहित के प्रति समर्पित बनाता गया विधि के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत लगन और ईमानदारी के बल पर एक विशिष्ट पहचान स्थापित की आज वे सुप्रीम कोर्ट ऑफ द्वठुस्त्रद्बड्डु में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं और न्याय के लिए निरंतर संघर्षरत हैं। उनके लिए वकालत केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व है एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए वे समाज के कमजोर वंचित और जरूरतमंद वर्ग को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं समाज सेवा के प्रति उनकी गहरी निष्ठा उन्हें सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय बनाती है वर्ष 2017 में Delhi Municipal Corporation Election 2017 के दौरान जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने उन्हें पटेल नगर नई दिल्ली से निगम पार्षद पद के लिए प्रत्याशी हेतु टिकट दिया यद्यपि वे इस चुनाव में सफल नहीं हो सके लेकिन इस अनुभव ने उनकी जनसेवा की भावना को और अधिक प्रबल किया तथा उन्हें समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को और निकट से समझने का अवसर प्रदान किया रवि भूषण चौबे द्वारा स्थापित Ravi Babita Support Foundation आज समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह संस्था निःशुल्क विधिक सहायता शिक्षा के प्रसार और niversal Humanity Mission के अंतर्गत मानवता के मूल्यों को सुदृढ़ करने का कार्य कर रही है। दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा में भी संस्था की सक्रिय उपस्थिति उनके कार्यों के व्यापक प्रभाव और दूरदर्शी सोच को दर्शाती है।उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा उनके माता-पिता, स्वर्गीय श्री गुप्तेश्वर चौबे और स्वर्गीय श्रीमती जयंती देवी के संस्कार रहे हैं जिनका आशीर्वाद उन्हें हर कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता रहा है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बबीता कुमारी चौबे जो स्वयं एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके प्रत्येक प्रयास में सशक्त सहयोग और प्रेरणा प्रदान करती हैं। उनके बच्चे–पुत्री रीतिका अधिवक्ता पुत्र शिवांग बी.ए. एलएल.बी. छात्र एवं सामाजिक कार्यकर्ता और पुत्र शौर्य कात्यायन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में संलग्न भी अपने-

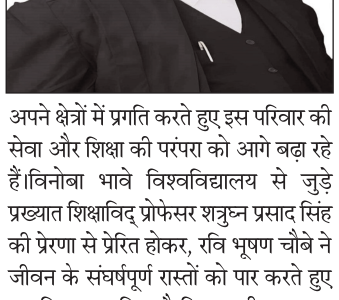

अपने क्षेत्रों में प्रगति करते हुए इस परिवार की सेवा और शिक्षा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।विनोबा भावे विश्वविद्यालय से जुड़े प्रख्यात शिक्षाविद् प्रोफेसर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की प्रेरणा से प्रेरित होकर, रवि भूषण चौबे ने जीवन के संघर्षपूर्ण रास्तों को पार करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं बल्कि समाज के लिए किए गए योगदान में निहित होती है। उनका जीवन आज के युवाओं के लिए एक जीवंत प्रेरणा है यह संदेश देता है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही सच्चे अर्थों में सफलता है।

अंततः, अधिवक्ता रवि भूषण चौबे की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस विचारधारा की विजय है जिसमें न्याय को केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया है—और जिसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही उनका जीवन लक्ष्य है संपर्क सूत्र (Contact Details): न्याय एवं समाज सेवा से जुड़े किसी भी परामर्श, सहयोग अथवा मार्गदर्शन के लिए अधिवक्ता रवि भूषण चौबे (Advocate, Supreme Court of India) से निम्न पते एवं संपर्क माध्यमों के द्वारा संपर्क किया जा सकता है– चेम्बर नं. 4, पीपल ब्लॉक, ट्रेज़री ऑफिस के निकट, गेट नं. 3, तिस हज़ारी कोर्ट्स, दिल्ली - 110054 मोबाइल: 9711422543, 9953107357

संजय गांधी नेशनल पार्क में 'अवैध मजार' पर वन विभाग का एक्शन

● लैंड जिहाद के लिए वन विभाग इलाके में कौन बनाया अवैध मजार?

कब से चल रही थी अवैध धार्मिक गतिविधियां?

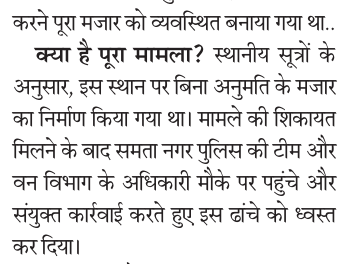

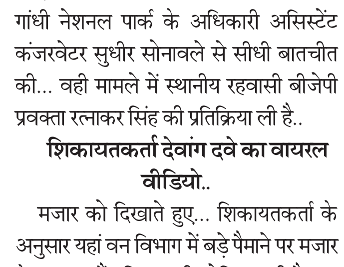

मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर...मुंबई बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क के संरक्षित वन क्षेत्र में एक कथित अवैध मजार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मजार पर लंबे समय से धार्मिक गतिविधियां और नमाज़ अदा की जा रही थी, जबकि यह इलाका पूरी तरह से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज़ोन के अंतर्गत आता है.. कांदिवली पूर्व समता नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इस इलाके को जानूपाड़ा मैदान कहते है जिसके ऊपर फॉरेस्ट विभाग के अंदर काफी समय से यहां मजार बनाकर यहां धार्मिक अनुष्ठान करने और सरकारी जमीन को कब्जा करने का मामला सामने आया था, स्थानीय रहवासी देवांग दवे के अनुसार यह मजार काफी पुराना है, वन विभाग ने पहले भी इस मजार को लेकर तोड़क कार्रवाई की थी लेकिन फिर दुबारा यहां निर्माण कार्य करने पूरा मजार को व्यवस्थित बनाया गया था..

क्या है पूरा मामला? स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इस स्थान पर बिना अनुमति के मजार का निर्माण किया गया था। मामले की शिकायत मिलने के बाद समता नगर पुलिस की टीम और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस ढांचे को ध्वस्त कर दिया।

अब उठ रहे हैं बड़े सवाल

इस घटना के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं– आखिर संरक्षित वन क्षेत्र में यह ढांचा कैसे बना? इतने समय तक यहां गतिविधियां कैसे चलती रहीं? संबंधित विभागों की नजर इससे कैसे चूक गई?

इस अवैध निर्माण को लेकर हमने संजय गांधी नेशनल पार्क के अधिकारी असिस्टेंट कंजरवेटर सुधीर सोनावले से सीधी बातचीत की... वही मामले में स्थानीय रहवासी बीजेपी प्रवक्ता रत्नाकर सिंह की प्रतिक्रिया ली है..

शिकायतकर्ता देवांग दवे का वायरल वीडियो..

मजार को दिखाते हुए... शिकायतकर्ता के अनुसार यहां वन विभाग में बड़े पैमाने पर मजार के नाम पर लैंड जिहाद की कोशिश जारी है..बार बार एक्शन के बाद भी जिहादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है... फिलहाल, प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल है और अब सभी की नजर इस पर है कि इस पूरे मामले में आगे क्या जांच और खुलासे होते हैं।